शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 49 वां वर्ष

ई-पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 49 अंक-1 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 25-1 जनवरी 2024 मूल्य पांच रूपये

क्या कांग्रेस लोस की चारों सीटें जीत पायेगी?

✔ सरकार के फैसलों और योजनाओं का दम भरने वाला कोई भी मंत्री उम्मीदवार बनने को तैयार होगा

✔ नये मंत्रियों को अब तक विभागों का आवंटन न हो पाना क्या सरकार के अन्दर का आईना नहीं है।

शिमला/शैल। क्या सुक्खू सरकार और कांग्रेस संगठन प्रदेश की चारों सीटों पर जीत दर्ज कर पायेगी? यह सवाल पिछले दिनों प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की दिल्ली में हाईकमान द्वारा बलायी गयी बैठक के बाद चर्चा में आया है। क्योंकि हाईकमान ने कांग्रेस की सरकार होने के नाते चारों सीटें जीतने का लक्ष्य सरकार को दिया है। हाईकमान कि यह अपेक्षा अव्यवहारिक भी नहीं है। क्योंकि कांग्रेस ने भाजपा सरकार के समय दो नगर निगमों और फिर मंडी लोकसभा के उपचुनाव में जीत हासिल की है। ऐसे में आज कांग्रेस की सरकार की परीक्षा होगी यह आने वाले लोकसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने एक प्रतिशत से भी कम अंतर से जीते हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस एक वर्ष में सरकार ने अपनी वर्किंग से भाजपा को और कितना हशिये पर धकेला है। स्मरणीय है कि जब सुक्खू सरकार ने सत्ता संभाली थी तब जनता के सामने प्रदेश के हालात श्रीलंका जैसे होने की चेतावनी दी थी। इसी चेतावनी के परिदृश्य में पिछली सरकार के अंतिम छः माह में लिये फैसले बदलते हुये छः सौ से अधिक संस्थान बंद कर दिये। चुनाव में दी गारंटियों पर यह कहा कि पांच वर्षो में उन्हें पूरा किया जायेगा। प्रदेश की जनता के सामने श्रीलंका जैसे हालात हो जाने की स्थिति रखी गयी थी। तब यह उम्मीद बंधी थी कि सरकार अपने अनावश्यक खर्चो पर लगाम लगाते हुये एक उदाहरण प्रस्तुत करेगी। लेकिन जब ऐसे वक्तव्य के बाद मंत्रिमंडल के पहले विस्तार से दो घंटे पूर्व छः मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियां कर दी तब जनता को पहला झटका लगा। उसके बाद जब एक दर्जन से अधिक गैर विधायकों को कैबिनेट रैंक में सलाहकार प्रधान सलाहकार और ओएसडी बनाकर ताजपोशियां की गयी तब दूसरा झटका लगा। सरकार की कथनी और करनी पर सवाल उठने शुरू हो गये क्योंकि ऐसी नियुक्तियों की न कोई राजनीतिक आवश्यकता थी और न ही प्रशासनिक। इन नियुक्तियों पर अनचाहे ही यह संदेश चला गया है कि मुख्यमंत्री अपने मित्रों के ज्यादा दबाव में आ गये हैं। वितिय मुहाने पर स्थिति संभालने के लिये पेट्रोल-डीजल पर वैट बढ़ाने के साथ ही हर सेवा और वस्तु के दाम बढ़ा दिये गये। जिस महंगाई से लोग निजात पाने की उम्मीद कर रहे थे उसे और बढ़ाने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। यही नहीं प्रदेश को कर्ज के चक्रव्यूह में डालने का जो आरोप पूर्व सरकार को लगाया जा रहा था उसे स्वयं कर्ज लेकर और आगे बढ़ा दिया गया। अब तक के कार्यकाल में ही बारह हजार करोड़ से अधिक का कर्ज ले लिया गया है। इतना कर्ज लेने के बाद भी कर्मचारियों को समय पर वेतन और पैन्शन का भुगतान नहीं हो पा रहा है। कैग ने भी 2022-23 की अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया है कि 2022-23 की अंतिम तिमाही में ज्यादा कर्ज लेने से इस वित्तीय वर्ष का कर्ज बड़ा है। जबकि नियमों के अनुसार सरकार अपने राजस्व के लिये कर्ज नहीं ले सकती। ऐसे में यह सवाल आने वाले समय में उठेगा ही की आखिर इतना कर्ज खर्च कहां किया गया। प्रशासनिक स्तर पर सुक्खू सरकार ने उसी शीर्ष प्रशासन को यथा स्थान बनाये रखा जो भाजपा का विश्वस्त था। यह सब व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर किया गया। यह प्रशासन जनता के प्रति कितना संवेदनशील और जवाबदेह रहा है उसका एक उदाहरण डीजीपी कुंडू प्रकरण में सामने आ गया है। राजनीतिक मंच पर सरकार और संगठन में किस तरह का तालमेल है यह कांग्रेस अध्यक्षा और पूर्व अध्यक्षों कुलदीप राठौर तथा कॉल सिंह ठाकुर के ब्यानों से सामने आता ही रहा है। इन संबंधों की पुष्टि अब नव नियुक्त मंत्रियों को अब तक विभागों का बंटवारा न हो पाने से हो जाती है। युवाओं को कितना रोजगार यह सरकार अब तक दे पायी है इसका खुलासा विधानसभा में इस आश्य के आये सवाल के उत्तर से हो जाता है। जिसमें कहा गया कि अभी सूचना एकत्रित की जा रही है। इस वस्तुस्थिति में आने वाले लोकसभा चुनाव के लिये कांग्रेस का कौन सा कार्यकर्ता चुनाव में जीत का वायदा करके उम्मीदवार बनने को तैयार हो पायेगा। कार्यकर्ताओं में चल रही चर्चाओं को यदि अधिमान दिया जाये तो संभव है कि उनकी ओर से यह सुझाव आ जाये कि सरकार की जिन योजनाओं और फैसलों को जनता में ले जाने की बात कर रहे हैं उन्हें जनता को अच्छे से समझा पाने में मंत्रियों से ज्यादा उपयुक्त कौन हो सकता है। इसके लिये हर सीट से किसी मंत्री को ही उम्मीदवार बनाया जाये और यह काम शीर्ष से ही शुरू हो। यदि कोई मंत्री उम्मीदवार बनने के लिये अपनी इच्छा से तैयार नहीं होता है तो उसी से सरकार की कथनी और करनी सामने आ जायेगी।

आर.टी.आई. आवेदन पर नगर निगम शिमला सवालों में

शिमला/शैल। नगर निगम शिमला परिक्षेत्र में हो रहे निर्माणों की वैधता के लिये नगर निगम प्रशासन ही पूरी तरह जिम्मेदार है। क्योंकि निर्माण संबंधी कोई भी नक्शा निगम प्रशासन के अनुमोदन के बिना व्यवहारिक रूप नहीं ले सकता। यहां तक की सरकारी निर्माण को भी टीसीपी अधिनियम के प्रावधान के मुताबिक इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। धर्मशाला के मकलोड़गंज प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया हुआ है ऐसे में किसी भी निर्माण के लिए आये नगरों की सारी औपचारिकताओं की जानकारी

निकाय के पास होना अनिवार्य है। ऐसी जानकारी को कोई भी व्यक्ति आरटीआई के तहत हासिल कर सकता है। जब से एनजीटी ने शिमला में निर्माण को लेकर कुछ प्रतिबंध और कुछ शर्ते लगायी हैं तब से यहां के निर्माण पर आम आदमी का ध्यान भी केंद्रित होना शुरू हो गया है। ऐसे में अगर निगम किसी आरटीआई आवेदन का तय समय पर जवाब न दे और अपील अधिकारी को इसके लिये

शेष पृष्ठ 8 पर.....

सरकारी योजनाओं का समयबद्ध लाभ सुनिश्चित करना विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य: राज्यपाल

शिमला/शैल। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अन्तर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाभार्थियों के साथ संवाद किया जिसका सीधा प्रसारण यहां राजभवन में किया गया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से ग्रामीण स्तर पर विकास का महोत्सव का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का आहवान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिलने से लोगों के विश्वास में वृद्धि हुई है। इस यात्रा के दौरान उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत 4.50 लाख नए लाभार्थी जोड़े गये हैं और एक करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड तैयार किए गए हैं। इसके अलावा 1.25 करोड़ लोगों की चिकित्सा जांच की गई। अभी तक देश में 1.25 लाख ग्राम पंचायतों से गुजर कर इस यात्रा में देश के 5 करोड़ से अधिक लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है।

इस अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में देश के लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों को सरकारी योजनाओं से होने वाले लाभ से अवगत करवाना तथा इनका समयबद्ध लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचाना है।

राज्यपाल ने कहा कि इस यात्रा को जनता का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। प्रधानमंत्री निरंतर लाभार्थियों तक पहुंचकर, उनके अनुभवों को जानकर सरकार की पहल और प्रमुख योजनाओं की सफलता सुनिश्चित कर रहे हैं।

विकसित भारत संकल्प यात्रा देश की लगभग ग्राम पंचायत को कवर करेगी। इसके तहत हिमाचल प्रदेश के 3799 स्थानों को लक्षित किया गया है और अब तक 85 खंडों की 2966 ग्राम पंचायतों में यह यात्रा पहुंची है। यात्रा के पहले चरण में चंबा जिला के पांगी क्षेत्र तथा जनजातीय लाहौल-स्पीति और किन्नौर के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में स्वच्छता, वित्तीय सेवाएं, बिजली, एल.पी.जी. कनेक्शन, मकान, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छ जल इत्यादि क्षेत्र शामिल है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में राज्य सरकार की दो महत्वाकांक्षी योजनाएं मुख्यमंत्री हिमकेयर स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना को भी शामिल किया गया है।

राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर राजभवन में उपस्थित रहे।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकानाएं दी

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को नववर्ष-2024 की शुभकामनाएं दी हैं।

अपने शुभकामना संदेश में राज्यपाल ने आशा व्यक्त की कि नववर्ष प्रदेशवासियों के जीवन में खुशी और उत्तम स्वास्थ्य लाएगा और हिमाचल प्रदेश विकास के सभी क्षेत्रें में प्रगति करेगा।

प्रदेशवासियों के नाम अपने बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि नववर्ष-2024 उनके जीवन में खुशियां और समृद्धि लेकर आयेगा। उन्होंने प्रदेश की जनता को नववर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आशा व्यक्त की है कि लोगों की सक्रिय भागीदारी और समर्पण से वर्ष-2024 में हिमाचल प्रदेश विकास के हर क्षेत्र में नये आयाम स्थापित करेगा।

मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को नववर्ष की शुभकामनाएं दी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट कर उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दी।

मुख्यमंत्री ने नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि यह वर्ष प्रदेशवासियों के लिए सुख और समृद्धि लायेगा।

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कैबिनेट मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, प्रो. चंद्र कुमार, रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह, विक्रमादित्य सिंह, राजेश धर्माणी और यादविंद्र गोमा भी इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ थे। उन्होंने भी राज्यपाल को नववर्ष की शुभकामनाएं दीं।

इससे पहले, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पी.एस. राणा, हिमाचल प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त आर.डी. धीमान, हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. श्रीकांत बाल्दी और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और प्रमुख लोगों ने इस अवसर पर राज्यपाल को बधाई दी।

पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी राजभवन में राज्यपाल से भेंट की और उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दीं।

राजभवन के सभी सदस्यों और राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारियों ने राज्यपाल और लेडी गवर्नर श्रीमती जानकी शुक्ल का अभिनंदन किया और उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दी।

राज्यपाल ने शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुये आशा व्यक्त की कि वर्ष 2024 सभी के जीवन में समृद्धि, उन्नति और खुशहाली लाएगा।

प्रदेश के छः प्रमुख कार्यालय सरकारी भवन में होंगे स्थानांतरितः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। राज्य सरकार ने प्रदेश के प्रमुख सरकारी विभागों को खाली पड़ी टूटीकंडी बाईपास पर स्थित पार्किंग कॉम्पलेक्स की ईमारत में स्थानातरित करने के निर्देश दिये हैं। सरकार ने, महिला एवं बाल विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग, आबकारी एवं काराधान विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य आयोग, ऊर्जा निदेशालय और हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक कार्यालय के आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली को जनवरी, 2024 तक किराये के आवासों से टुटीकंडी पार्किंग कॉम्पलेक्स शिमला में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं। इस निर्णय का उद्देश्य लबे समय से खाली पड़े भवन का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के साथ-साथ सार्वजनिक खर्चों में भी कटौती भी करना है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान में पुलिस हेल्पलाइन का कार्यालय पहले से ही बहुमंजिला पार्किंग टूटीकंडी में कार्यशील है और अब छः अतिरिक्त विभाग इस इमारत से संचालित होंगे। प्रदेश सरकार जनता के धन का उचित उपयोग सुनिश्चित कर रही है। सरकार के इस निर्णय से सार्वजनिक धन से निर्मित भवन का उपयोग सुनिश्चित होने के साथ-साथ इन सरकारी कार्यालयों के लिए किराए के आवास पर खर्च किए जा रहे प्रति माह 10 लाख रुपये से अधिक के धन की भी बचत होगी।

मुख्यमंत्री के निर्देशों की अनुपालना करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने संबंधित विभागों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप भवन की आन्तरिक सज्जा की जरूरतों को देखा लोक निर्माण विभाग ने कार्यालयों की आवश्यकता के अनुरूप भवन में परिवर्तन कर, इसे कार्यालय के रूप में उपयोग के लिए तैयार किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इन छह विभागों को नए भवन में कामकाज शुरू करने के लिए शीघ्र बिजली और पानी के कनेक्शन के लिए आवेदन करने के निर्देश दिए हैं।

तोल एवं माप उपकरणों के सत्यापन एवं मोहरांकन से 3.83 करोड़ रुपये शुल्क एकत्रित

शिमला/शैल। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक एवं नियंत्रक विधिक माप विज्ञान राम कुमार गौतम की अध्यक्षता में विधिक माप विज्ञान संगठन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान संगठन द्वारा किए गए कार्यो की समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि संगठन ने इस वित्त वर्ष के दौरान 30 नवम्बर, 2023 तक प्रदेश में कुल 8747 व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निरीक्षण किए व 945 प्रतिष्ठानों के विरुद्ध विधिक माप विज्ञान अधिनियम-2009 व अंतर्गत निर्मित नियमों के तहत चालान दर्ज किए। उन्होंने बताया कि 879 प्रतिष्ठानों से विभागीय समझौते के तहत 24,68,000 रुपये की राशि एकत्रित की गई। विभाग द्वारा इस वित्त वर्ष में 2,52,722 तोल एवं माप उपकरणों के सत्यापन एवं मोहरांकन से 3,83,42,881 रुपये शुल्क के रूप में एकत्रित किए गए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वह अपने-अपने कार्यक्षेत्र में उपभोक्ताओं के हितों का विशेष ध्यान रखें और पैट्रोल पंप, घरेलू गैस, आभूषणों, मिठाई व अन्य रोजमर्रा की वस्तुओं से संबंधित निरीक्षण समय-समय पर करते रहें व अनियमितता पाए जाने पर उचित कार्रवाई करें।

उन्होंने कहा कि विधिक माप विज्ञान संगठन उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कार्य करता है। किसी भी प्रकार की वस्तुओं को कम तोलने व अंकित मूल्य से अधिक वसूलने पर संगठन द्वारा दोषी के विरुद्ध नियमों के तहत कारवाई की जाती है। ऐसी किसी भी शिकायत हेतु राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाईन नम्बर 1800-11-4000 या 1915, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प नम्बर 1100 तथा 1967 पर संपर्क कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त व्यापरियों की सुविधा हेतु संगठन द्वारा जारी की जाने वाली विज्ञप्तियों एवं पंजीकरण के लिए online web portal www.hpwm.hp.gov.in की सुविधा सुचारू रूप से प्रदान की जा रही है।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादकःजे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

ठियोग में आपदा प्रभावितों को 22.81 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस वर्ष बरसात के दौरान भारी बारिश, भू-स्खलन तथा बाढ़ से आई आपदा से प्रभावित परिवारों के 'पुनर्वास' के लिए जिला करोड़ रुपये की धनराशि जारी की। आपदा के दौरान जिला शिमला में 395 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 458 कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा है तथा 354 किसानों को पशुधन का नुकसान हुआ है।

शिमला के आपदा प्रभावितों को ठियोग के आलू ग्राउंड में 22.81 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की। पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए घरों के लिए मुआवजा राशि के रूप में 395 प्रभावित परिवारों को प्रथम किस्त के रूप में 3-3 लाख रुपये के तौर पर 11.85 करोड़ रुपये तथा अन्य 1840 प्रभावितों को 10.96

विधायक कुलदीप राठौर ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से आपदा के लिए कोई आर्थिक मदद नहीं मिली लेकिन राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों की मदद के लिए राहत राशि में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है।

एक जनवरी 2024 से सरकारी विभाग नहीं खरीदेंगे डीजल-पैट्रोल वाहन:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने तथा ई-वाहनों को प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी सरकारी विभागों को एक जनवरी, 2024 से डीजल या पैट्रोल वाहन न खरीदने के निर्देश दिए हैं। अति-आवश्यक होने पर केवल प्रदेश मंत्रिमण्डल की स्वीकृति के बाद ही विभाग पैट्रोल या डीजल वाहनों की खरीद कर सकेंगे।

अपने पहले बजट में ही ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए विद्युत चालित वाहन ई-वाहन पर राज्य सरकार का विज़न स्पष्ट किया और आगे बढ़कर स्वयं भी इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग कर मिसाल पेश की। राज्य सरकार के प्रयासों के कारण ही आज सरकारी ई-वाहनों की संख्या 185 हो गई है, जबकि प्रदेश में पंजीकृत निजी इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 2733 तक पहुंच गई है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा ''राज्य सरकार हिमाचल में ई-व्हीकल को बढ़ावा दे रही है। परिवहन विभाग पहला ऐसा विभाग है, जिसमें ई-वाहन का उपयोग शुरू किया गया तथा चरणबद्ध तरीके से सभी सरकारी महकमों में भी इन वाहनों का संचालन सुनिश्चित किया जा रहा है। ई-वाहन केवलमात्र एक नई शुरूआत नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें पर्यावरण को सुरक्षित बनाना होगा तथा इसकी शुरूआत आज से ही करनी होगी।''

सरकारी विभागों में गाड़ियों की आवश्यकता पूरी करने के लिए राज्य सरकार ने ई-टैक्सी अनुबंध पर लेने की अनुमति प्रदान की है। 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत युवाओं को ई-टैक्सी के परमिट प्रदान किए जा रहे हैं। ई-टैक्सी की खरीद पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी भी दी जा रही है। इन गाड़ियों को घर पर भी चार्ज किया जा सकता है तथा राज्य सरकार भी चार्जिंग के लिए आधारभूत ढांचा तैयार कर रही है। ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 6 राजमार्गो को ग्रीन कोरिडोर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में ई-वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए परिवहन विभाग ने 54 स्थानों को अंतिम रूप दिया है, जिनमें से कुछ लगभग बनकर तैयार हैं।

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की सभी डीजल गाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से ई-बसों में बदला जा रहा है। हाल ही में ई-बसें बनाने वाली कंपनियों के साथ बैठक में हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप गाड़ियां तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा ''राज्य सरकार लंबे रूटों पर भी ई-बसें चलाने जा रही है। एचआरटीसी के बेड़े में टाइप-1, 2 और 3 ई-बसों को चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जा रहा है, ताकि 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल को स्वच्छ व हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके।

राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना चरण-2 शुरू करने का निर्णय

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में युवाओं को सशक्त बनाने व स्वच्छ ऊर्जा पहल को आगे बढ़ाने के दृष्टिगत सौर ऊर्जा के दोहन के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के चरण-2 को शुरू करने का

निर्णय लिया गया। यह योजना 100 किलोवाट से 500 किलोवाट तक क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने पर केंद्रित है। यह योजना राज्य के अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने में मील पत्थर साबित होगी। यह योजना 21 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं को उद्यमशीलता के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ कौशल विकास को प्रोत्साहित करेगी।

योजना के तहत प्रतिभागियों को तीन बीघा भूमि पर 100 किलोवाट क्षमता की परियोजना स्थापित करने के लिए 25 वर्षो तक लगभग 20,000 रुपये मासिक आय और क्रमश: पांच और दस बीघा भूमि में स्थापित की जाने वाली 200 किलोवाट और 500 किलोवाट क्षामता की परियोजनाओं के लिए 40,000 रुपये व एक लाख प्रतिमाह मासिक आय प्राप्त होगी।

योजना के तहत, वित्तपोषण में राज्य सरकार द्वारा 70 प्रतिशत बैंक ऋण उपलब्ध करवाने में सहायता और राज्य सरकार द्वारा 30 प्रतिशत इक्विटी प्रदान की जाएगी। सौर ऊर्जा डेवलपर को केवल 10 प्रतिशत जमानत राशि जमा करवानी होगी। यह जमानत राशि 25 वर्षो के उपरान्त डेवलपर को वापिस कर दी जाएगी।

मंत्रिमण्डल ने 8 जनवरी, 2024 से पूरे राज्य में 'सरकार गांव के द्वार' शुरू करने को भी स्वीकृति प्रदान की। इस दौरान 12 फरवरी, 2024 तक गांवों के समूहों में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद किया जाएगा।

सस्ती दरों पर बागवानी उपकरण, खाद और कीटनाशक उपलब्ध करवाएगी प्रदेश सरकार:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार बागवानी क्षेत्र को सुदृढ़ करने तथा बागवानों की आय बढ़ाने की दिशा में अनेक निर्णय ले रही है। इसी के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2024 से बागवानी उपज विपणन एवं प्रसंस्करण निगम एचपीएमसी के माध्यम से सस्ती दरों पर बागवानी उपकरण, खाद और कीटनाशक उपलब्ध करवाए जाएंगे।

बागवनी क्षेत्र के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा कि एचपीएमसी ने अपने मुनाफे को 15 प्रतिशत से घटाकर नौ प्रतिशत किया है, जिससे सेब उत्पादकों की सस्ते व गुणात्त्मक उत्पादों तक पहुंच संभव हुई है।

इसके अतिरिक्त, एचपीएमसी ने किसानों को सस्ती दरों पर जरूरी सामान उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से उत्पादक कंपनियों से सीधी खरीद करने के लिए 38 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सेब उत्पादकों की सहायता के लिए वचनबद्ध है और एचपीएमसी के मुनाफे में कमी का निर्णय बागवानी समुदाय के उत्थान तथा हिमाचल के सेब उत्पादकों के कल्याण के प्रति हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार 'व्यवस्था परिवर्तन' की भावना से कार्य कर रही है और प्रत्येक निर्णय जनकल्याण के लिए लिया जा रहा है। प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रदेश का हर वर्ग इन योजनाओं से लाभान्वित हो। उन्होंने कहा कि बागवानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से वर्तमान योजनाओं में यथोचित सुधार करके इन्हें अधिक प्रभावशाली बनाया जा रहा है।

प्रदेश सरकार ने अपने पहले बजट में एचपीएमसी के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बागवानी उत्पाद खरीदने के लिए ऑनलाइन प्रणाली स्थापित करने का प्रावधान किया है। यह ऑनलाइन सुविधा निगम के वातानुकूलित भण्डारों की बुकिंग के लिए भी उपलब्ध होगी। इससे घर से उपज की बिक्री के अतिरिक्त किसान एचपीएमसी द्वारा बेचे जा रहे उपकरण व अन्य सामग्री भी ऑनलाइन ही बुक कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान उत्पादक संगठनों के सहयोग से किन्नौर के भावानगर, चिड़गांव के समीप संदासू, जुब्बल के अणु, शिमला के चौपाल व खड़ापत्थर, सोलन जिला के जाबली, मंडी के सुन्दरनगर तथा रामपुर बुशहर के दत्तनगर में ग्रेडिंग व पैकिंग हाउस, वातानुकूलित व शीत भण्डार स्थापित किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस वर्ष सेब उत्पादकों की सुविधा के दृष्टिगत किलोग्राम की दर से सेब बिक्री सुनिश्चित की है जिससे सेब उत्पादकों की चिरलम्बित मांग पूरी हुई है। साथ ही सेब बागवानों के लाभ में भी वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले सेब सीजन में यूनिवर्सल कार्टन में सेब की बिक्री सुनिश्चित की जाएगी।

सिरमौर दौरे पर करेंगे अनुसूचित जनजाति दर्जे की औपचारिक घोषणा:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। सिरमौर जिला के हाटी समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू

से भेंट कर समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित करने के लिए आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ है और राज्य सरकार ने इस संबंध में अविलम्ब अधिसूचना जारी कर दी।

उन्होंने कहा कि 3 जनवरी, 2024 को सिरमौर जिले के अपने प्रस्तावित दौरे के दौरान वह हाटी समुदाय को इस दर्जे की औपचारिक घोषणा करेंगे।

इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और समुदाय के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

बनखंडी में 619 करोड़ रुपये की लागत से एक प्राणी उद्यान पार्क स्थापित किया जाएगा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कांगड़ा जिले के देहरा उपमंडल के बनखंडी में 619 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक अत्याधुनिक प्राणी उद्यान स्थापित किया जाएगा। यह परियोजना तीन चरणों में विकसित की जाएगी और दिसम्बर, 2024 तक इसके पहले चरण को कार्यशील करने की योजना है। इस प्राणी उद्यान में पर्यटकों को प्रदेश की समद्ध जैव विविधता का अविस्मरणीय अनुभव प्राप्त होगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का सफल कार्यान्वयन प्रधान मुख्य वन्य अरॉयपाल पीसीसीएफ वन्य जीव एवं मुख्य वन्य जीव वार्डनसीडब्ल्यूएलडब्ल्यू के नेतृत्व में एक संचालन समिति सुनिश्चित करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र की पर्यटन क्षमता का समुचित दोहन करने के उद्देश्य से इस प्राणी उद्यान के डिजाइन में क्षेत्र की विविध पर्यटन क्षमताओं का समावेश किया गया है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कांगड़ा जिले को राज्य की पर्यटन राजधानी बनाने में यह परियोजना मील पत्थर साबित होगी।

प्राणी उद्यान पार्क का मास्टर ले-आउट प्लान और प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इस परियोजना को तैयार करने में पर्यावरण-अनुकूल प्रौद्योगिकियों, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और कुशल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को शामिल किया गया है।

इस पार्क में ओरिएंटेशन सेंटर, वॉक-इन एवियरी, प्रदर्शनी और थीम आधारित जोन जैसे काम्यक वन, दैवत्व वन, चित्रकूट, दंडक वन के अनुभव आगंतुकों के लिए आकर्षण का मुख्य केन्द्र होंगे। उद्यान में एक्वाटिक जोन, नॉक्टर्नल हाउस और मोनोरेल में सफारी इत्यादि विविध आकर्षण भी शामिल किए गए हैं।

पार्क में एक कैफेटेरिया, भ्रमण क्षेत्र, जैव विविधता कोर्ट और हिमाचल की संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने वाला एक इको विलेज भी स्थापित किया जाएगा। पर्यावरण-अनुकूल पतियों को बढ़ावा देते हुए इस परियोजना में रीसाइक्लिंग प्रणालियां शामिल की जाएंगी।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।

शिलान्यास और उद्घाटन पट्टिकाएं तोड़ने वालों पर दर्ज होगी एफआईआर:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में शिलान्यास और उद्घाटन पटिकाओं को तोड़ने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ी गई लोकार्पण पटिका की घटना की निंदा की है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज एफआईआर करने और क्षतिग्रस्त पट्टिकाओं को पुन: स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार इस प्रकार के मामलों से सख्ती से निपटेगी।

जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते।..... स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

कांग्रेस क्यों मौन है?

इस समय केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। इस यात्रा के माध्यम से मोदी सरकार की योजनाएं और उनके लाभ जनता को परोसे जा रहे हैं। इस यात्रा के समापन के साथ ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन भी किया जा रहा है। संभव है कि इन आयोजनों के साथ ही लोकसभा चुनावों की भी घोषणा कर दी जाये। क्योंकि नरेंद्र मोदी विपक्ष को व्यवहारिक रूप से एकजुट होने का कम से कम समय देना चाहेंगे। इस समय विपक्ष का इन आयोजनों के राजनीतिक पक्षों की ओर बहुत कम ध्यान है। ऐसे में इस यात्रा में योजनाओं को लेकर जो कुछ परोसा जाएगा आम आदमी उसी पर भरोसा करने और उसे सच मानने लग जाएगा। यह भी संभावना बनी हुई है कि इन योजनाओं और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश को धर्मनिरपेक्ष की जगह धार्मिक देश भी घोषित कर दिया जाए। क्योंकि अब की बार 400 पार का जो लक्ष्य देश के सामने परोसा गया है वह तभी पूरा हो सकता है जब राजनीतिक और आर्थिक प्रश्नों को पीछे धकेलते हुए धार्मिक प्रश्न को बड़ा बना दिया जाए। राजनीति में संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता यह एक स्थापित सच है।

2024 का लोकसभा चुनाव कई मायनो में महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जब नए संसद भवन में प्रवेश के अवसर पर सांसदों को संविधान की प्रति दी गई थी तो उसकी प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष गायब था। इसी के बाद इंडिया बनाम भारत का द्वंद सामने आया। सनातन धर्म को लेकर विवाद उभरा। यह विवाद आज भी अपनी जगह बने हुए हैं। इन सवालों को उभार कर छोड़ दिया गया और सार्वजनिक बहस का विषय नहीं बनने दिया गया। इसी पृष्ठभूमि में पांच राज्यों के चुनाव और हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में कांग्रेस राहुल के सारे प्रयासों के बावजूद अप्रत्याशित रूप से हार गई। अब कांग्रेस की इस हार के बाद विपक्ष के गठबंधन में कांग्रेस की स्थिति कमजोर हो गई है। जिन राज्यों में गठबंधन के दलों की सरकार है वहां पर यह दल कांग्रेस को कोई अधिमान नहीं देना चाहते। यह व्यवहारिक और कड़वा सच बनता जा रहा है।

इस समय देश की आर्थिक स्थिति को लेकर जो आंकड़े सरकार की ओर से परोसे जा रहे हैं उनकी प्रमाणिकता पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं है। जबकि 80 करोड़ जनता को इतनी योजनाओं के बाद भी जब सरकारी राशन पर निर्भर रहना पड़ रहा है तो योजनाओं की प्रासंगिकता पर स्वत: ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अभी संसद से विपक्ष के 151 सांसदों को निलंबित कर दिया गया क्योंकि वह संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहे थे। सांसदों के इस निलंबन से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप स्वत: ही प्रमाणित हो जाता है। लेकिन इन प्रश्नों पर राज्यों में बैठे कांग्रेस और अन्य घटक दलों के नेता और कार्यकर्ता कितने मुखर हैं? हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार है और सरकार आने के बाद सरकार और संगठन इन प्रश्नों पर एकदम मौन साधे बैठे हैं। जब कांग्रेस की सरकार होते हुए भी कांग्रेसी भाजपा और मोदी सरकार के खिलाफ ऐसे मौन हैं तो जहां सरकारें नहीं है वहां क्या हाल होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।

अयोध्या उच्च आध्यात्मिकता से डिजिटल उत्कर्ष तक

अयोध्या - भगवान राम की जन्मस्थली और भारतीय सभ्यता के गहरे आध्यात्मिक महत्व का स्थल अयोध्या डिजिटल कायाकल्प और तकनीकी उत्कर्ष का अनुभव कर रहा है। जब से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शहर में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर की आधारशिला रखी है, तब से इस शहर ने विकास के एक नए युग की ओर कदम बढ़ा दिया है।

अयोध्या पहले से ही बुनियादी ढांचे के पुनरुत्थान के बीच में है। इस शहर को आध्यात्मिक केंद्र, वैश्विक पर्यटन केंद्र और भव्य स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। शहर में एक आगामी ग्रीनफील्ड टाउनशिप की भी योजना बनाई जा रही है जिसमें भक्तों के लिए आवास सुविधाएं, आश्रमों, मठों, होटलों, विभिन्न राज्यों के भवनों के लिए जगह शामिल होगी। एक पर्यटक सुविधा केंद्र, एक विश्व स्तरीय संग्रहालय भी बनाया जाएगा। सरयू नदी और उसके घाटों के आसपास बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरयू नदी पर क्रूज संचालन को भी नियमित सुविधा बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अयोध्या को एक ऐसा शहर बताया है जो हर भारतीय की सांस्कृतिक चेतना में बसा हुआ है। अयोध्या में हमारी सर्वोत्तम परंपराएं और सर्वोत्तम विकासात्मक बदलाव दिखना चाहिए। साथ ही, अयोध्या को प्रगति के अगले चरण में पहुंचाने का क्षण भी अब आ गया है। यह शहर वह स्थान बन रहा है जहां परंपराओं का तकनीकी प्रगति से जुड़ाव हो रहा है और जहां आध्यात्मिकता डिजिटल प्रगति से मिल रही है।

अयोध्या में डिजिटल लेनदेन का चलन बढ़ा

अयोध्या में अभी बड़े स्तर पर निर्माण कार्य चल रहा है। वहां की सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है और बहुस्तरीय कार पार्क सहित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, मंदिरों का नवीनीकरण किया जा रहा है तथा सरयू नदी पर घाटों को बेहतर बनाया जा रहा है। इस तरह शहर के कायापलट से वहां आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है, कभी शांत रहे शहर में अभी चहल-कदमी बढ़ गई है। सरयू नदी पर नाव चलाने वाले नाविकों से लेकर हनुमान गढ़ी में फूल और प्रसाद बेचने वाले विक्रेताओं तक, सभी शहर में तेजी से डिजिटल भुगतान करते दिख रहे हैं। सरयू नदी के तट पर लगभग 100 नाविकों में से एक अन्नू मांझी ने कहा कि डिजिटल भुगतान ने मेरे जीवन को आसान बना दिया है क्योंकि खुदरा पैसे के लिए इधर-उधर भागना नहीं पड़ता है। पैसा सीधे यूपीआई के माध्यम से मेरे बेटे के बैंक खाते में जाता है, जो हमारे लिए बहुत राहत की बात है।

पूरे अयोध्या में डिजिटल लेनदेन की ओर बदलाव स्पष्ट देखा जा सकता है। नदी के किनारे पूजा सामग्री बेचने वाले दुकानदार श्री रामधन यादव क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करते हैं, जिससे विक्रेताओं और ग्राहकों दोनों के लिए लेनदेन आसान हो जाता है। उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया, जब एक ग्राहक ने पूजा के सामान के लिए 100 रुपए का नोट दिया तो उन्होंने क्यूआर कोड की ओर इशारा करते हुए कहा कि रुपया ऑनलाइन भुगतान करें क्योंकि मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं, ग्राहक ने बात मानी और चेहरे पर मुस्कान लेकर दुकान से चला गया।

शाम की आरती के दौरान कनक भवन तक में काउंटरों पर क्यूआर कोड के माध्यम से दान आसानी से किया जाता है, जिससे भक्तों के लिए प्रक्रिया सरल हो जाती है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में, 2,000 रुपए तक का योगदान नकद रूप में किया जा सकता है, लेकिन इससे अधिक का योगदान ऑनलाइन ही किया जा सकता है, जो कि क्यूआर कोड के माध्यम से निर्बाध रूप से सुविधाजनक है।

अयोध्या कैंट के सदर बाजार इलाके में रहने वाले 40 वर्षीय मोहम्मद राशिद खान के मुताबिक, यूपीआई ने उनमें एक नया आत्मविश्वास पैदा किया है। उन्होंने कहा कि नकदी संभालना एक सिरदर्द था क्योंकि दैनिक सामान खरीदते समय कम पैसे की जरूरत होने पर खुदरा पैसा ढूंढना हमेशा एक समस्या थी। अब डिजिटल भुगतान के साथ, वह सिरदर्द दूर हो गया है और पैसा मेरे बैंक खाते में तुरंत और सुरक्षित रूप से पहुंच जाता है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर भारत का प्रयास

डिजिटल भुगतान की ओर यह बदलाव सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्र वीबीएसवाई के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, पीएम सुरक्षा बीमा, पीएम स्वनिधि जैसी प्रमुख केंद्रीय योजनाओं के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना सरकार के डिजिटल इंडिया दृ ष्टिकोण के अनुरूप भी है।

सभी हितधारकों के साथ सरकार के समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरूप हाल के वर्षो में डिजिटल भुगतान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ड भागवत किसनराव कराड ने बताया कि कुल डिजिटल भुगतान लेनदेन की संख्या वित्तीय वर्ष 2017-18 में 2,071 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 13,462 करोड़ हो गई है, जो कि 45 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर है। मौजूदा वित्त वर्ष में 01 अप्रैल, 2023 से 26 दिसंबर, 2023 तक कुल 12,020 करोड़ डिजिटल लेनदेन हुए हैं। 26 जुलाई, 2023 तक देश में 14.92 लाख से अधिक भीम आधार भुगतान पीओएस लगाए गए हैं। 26 जुलाई तक 33.69 करोड़ से अधिक भौतिक और मोबाइल पीओएस तैनात किए गए हैं। डीडी न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का डिजिटल लेनदेन हुआ है। डिजिटल लेनदेन एक नए विकसित भारत का प्रतीक बन गया है और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि डिजिटल पैसा गरीबों को सशक्त बनाएगा।

अयोध्या 23 जनवरी, 2024 को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भव्य उद्घाटन के लिए तैयार है। ऐसे में यह शहर न केवल बुनियादी ढांचे के रूप में बल्कि दुनिया भर से तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के स्वागत के लिए डिजिटल रूप से भी तैयार है। भौतिक शांति और आध्यात्मिक सांत्वना का जुड़ाव आगंतुकों को समय से परे अनुभव प्रदान करने और तकनीकी सुविधा के साथ आध्यात्मिकता का बेहतरीन अनुभव प्रदान करने का वादा करता है, जो कि अयोध्या के असाधारण पुनर्जागरण का प्रमाण है।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत सरकार के कैलेंडर 2024 का अनावरण किया

शिमला। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमारा संकल्प विकसित भारत की थीम के साथ भारत सरकार का कैलेंडर 2024 लॉन्च किया। कैलेंडर 2024 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के तहत जन अनुकूल नीतियों की रचना तथा योजनाओं और पहलों के कार्यान्वयन के माध्यम से भारत की जनता के जीवन में आए सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तन को दर्शाता है। इस अवसर पर अपने संबोधन में ठाकुर ने सरकार की कई उपलब्धियों को याद किया, जिनसे संबंधित तस्वीरें कैलेंडर के पन्नों की शोभा बढ़ा रही हैं।

ठाकुर ने कहा कि भारत ने आत्मनिर्भर बनने की दिशा में शानदार प्रगति की है। जो देश मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा आयातक था, वह आज दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। जो देश कभी वैक्सीन आयात करता था, वह अब वैक्सीन मैत्री के तहत पूरी दुनिया को वैक्सीन बांट रहा है। भारत आज विनिर्माण के क्षेत्र में अपार सफलता हासिल कर चुका है। उन्होंने कहा कि यहां तक कि जिन स्थानों पर भारत की उपस्थिति नगण्य थी, वहां भी भारत अब एक महत्वपूर्ण शक्ति बन चुका है। इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि भारत आज तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।

ठाकुर ने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण को सर्वोपरि मानती है और यह एक ओर उज्ज्वला योजना और दूसरी ओर ड्रोन दीदी के रूप में परिलक्षित होता है। किसान कल्याण

के विषय में, ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार ने ही स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू की। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सरकार ने किसानों की समृद्धि पर अब तक 2.8 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

पारदर्शिता एवं जवाबदेही इस सरकार के आदर्श हैं और इन्हीं मूल्यों ने एक समय पांच सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक माने जाने वाले भारत को आज दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की स्थिति तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इन मूल्यों की भावना का संचार शीर्ष स्तर से होता है।

एक आशावादी दृष्टिकोण के साथ अपने संबोधन का समापन करते हुए, ठाकुर ने कहा कि 2023 समाप्त होने के साथ ही 2024 अवसरों की एक नई सुबह लेकर आ रहा है। दुनिया भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है, दुनिया नेतृत्व के लिए भारत की ओर देख रही है।

इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री ने हमारा संकल्प विकसित भारत विषय पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया।

कैलेंडर के बारे में जानकारी

प्रत्येक महीना पिछले नौ वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए वादों को पूरा करने के माध्यम से महिलाओं, युवाओं, मध्यम वर्ग, किसानों और समाज के हर वर्ग के लोगों के चेहरों पर आयी मुस्कान को दर्शाता है। यह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के वादे को साकार करने के लिए कई सरकारी एजेंसियों और अधिकारियों द्वारा किए गए अथक प्रयासों के प्रति सम्मान व्यक्त करता है।

जनवरी

जब हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, हम वर्ष के पहले महीने के लिए संभावनाओं को बढ़ाना, भारत को आत्मनिर्भर बनाना की थीम पर नवाचार और मजबूती की भावना को अपनाते हैं। भारत ने मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड जैसी पहलों के कारण बेमिसाल सफलता अर्जित की है और जनवरी की थीम आत्मनिर्भर और सशक्त भविष्य की दिशा में हमारे सामूहिक प्रयासों की याद दिलाती है।

फरवरी

आगे बढ़ते हुए, हम फरवरी का उत्सव राष्ट्रीय विकास के लिए युवा शक्ति की थीम के साथ मनाते हैं। उद्यमिता को बढ़ावा देने से लेकर प्रौद्योगिकी को अपनाने तक, फरवरी युवाओं के योगदान को बढ़ाने, देश को एक उज्ज्वल और अधिक समावेशी भविष्य की ओर प्रेरित करने का आहवान करती है।

मार्च

गरीबों की सेवा और हाशिये पर रहने वाले लोगों का उत्थान करना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। मार्च महीने की थीम वंचितों को प्राथमिकता है, यह एक अनुस्मरण है कि सच्ची प्रगति उन लोगों को सहायता प्रदान करने में निहित है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। इसके लिए यह सुनिश्चित करना है कि हमारे कार्य और नीतियां समावेशिता एवं न्याय के प्रति समर्पण को प्रतिबिंबित करें।

अप्रैल

महिलाएं समाज में अहम भूमिका निभाती हैं, उनकी प्रगति के बिना समाज की समग्र प्रगति रुक जाती है। अप्रैल की थीम हर क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने, एक ऐसे भविष्य को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने को प्रोत्साहित करती है, जहां उनका नेतृत्व और योगदान निर्णय लेने एवं सतत विकास में महत्वपूर्ण हो सकता है।

मई

हमारे समर्पित किसानों के अविश्वसनीय काम को प्रमुखता देना, इस महीने का मुख्य आकर्षण है। यह कृषि उन्नति के लिए नीतियों, स्थायी तौर-तरीकों का समर्थन और देश के अन्नदाताओं का कल्याण, सुनिश्चित करने पर सरकार द्वारा दिए गए महत्व पर बल देता है।

जून

पिछले दस वर्षों में, पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा और मुद्रा योजना जैसी विभिन्न सरकारी पहलों से भारत में नौकरियों की संख्या, स्व-रोज़गार की संभावनाओं और व्यवसाय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस महीने की थीम रोजगार और स्व-रोजगार के अवसरों में वृद्धि के साथ रोजगार सृजन और उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसके फलस्वरूप आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है।

जुलाई

जुलाई हमारे समाज के मुख्य आधार, मध्यम वर्ग का उत्सव मनाने से संबंधित है। उनकी कड़ी मेहनत 'न्यू इंडिया' की भावना को परिभाषित करती है और वे विकास व नवाचार को बढ़ावा देने में सबसे आगे हैं। हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग के लाभ के लिए जीवन यापन में आसानी की दिशा में लगातार काम किया है।

अगस्त

अगस्त का महीना विश्व आर्थिक मंच पर भारत के बढ़ते महत्त्व को दर्शाता है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसी प्रमुख पहलों के साथ, भारत ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अपना मार्ग प्रशस्त किया है।

सितम्बर

अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आधुनिक अवसंरचना में महत्वपूर्ण निवेश से लेकर व्यापक परिवहन नेटवर्क तक, सितंबर माह देश की प्रगति के लिए एक सुदृढ़ आधारशिला निर्माण में पिछले दस वर्षों में देश द्वारा की गई परिवर्तनकारी कदमों का प्रमाण है।

अक्तूबर

अक्तूबर का महीना हमें देश के स्वास्थ्य ढांचे को सशक्त बनाने वाले आयुष्मान कार्डो, जन औषधि केंद्रों और नए एम्स व जिला अस्पतालों के साथ ही आम जन तक स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच तथा क्षमताओं में हुई बढ़ोतरी पर बल देकर स्वस्थ भारत के दृष्टिकोण का उत्सव मनाने के लिए आमंत्रित करता है।

नवम्बर

नवंबर की थीम हमारी अंतर्निहित जीवंत संस्कृति पर गर्व करने से लेकर विभिन्न कला रूपों को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक वंशावली को सशक्त करने के उद्देश्य से देश के सांस्कृतिक विरासत स्थलों को संरक्षित करने तथा समग्र एवं सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए हमारे मूल्यों व संस्कृति को सहेज कर रखने से संबंधित है।

दिसंबर

दिसंबर में भारत ने वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श वाक्य- एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य और मिशन लाइफ जैसी महत्वपूर्ण पहल के साथ विश्व मित्र के रूप में स्वयं को स्थापित किया है।

इस कैलेंडर को राष्ट्र के विकास और उन्नति के प्रति हमारे समर्पण को दैनिक आधार पर याद दिलाने के लिए भी तैयार किया गया है। यह कैलेंडर सभी को दृढ़ संकल्प, एकता और साझा दृष्टिकोण के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है और सभी भारतीयों को देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक संपन्न एवं विकसित भारत बनाने की दिशा में यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरणा देता है।

विकसित भारत संकल्प यात्रा:इंशा शाबिर की सपनों को साकार करने वाली कहानी

शिमला। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले की खूबसूरत घाटी में एक युवा महिला रहती हैं, जो आज आत्मनिर्भरता, विकास और परिवर्तन का प्रतीक बन गई हैं। पुलवामा के अरिगाम में एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाली इंशा शाबिर आज अपने कारोबार की मालकिन बन गई हैं और अपना बुटीक संभालती हैं। इंशा शाबिर केंद्र सरकार की दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की कई लाभार्थियों में से एक हैं, जो इंशा जैसी कई लड़कियों और महिलाओं को तरक्की की उड़ान भरने के लिए पंख प्रदान कर रही है।

वर्तमान में चल रही 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' के दौरान मीडिया को दिए एक साक्षात्कार में, इंशा ने कहा कि उसने वर्ष 2017 में पहली बार दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में सुना था और तुरंत इसके लिए पंजीकरण कराया था। यह योजना 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के लिए कुशल और प्रभावी संस्थागत मंच का निर्माण करना है, ताकि उन्हें स्थायी आजीविका वृद्धि और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच के माध्यम से उनकी घरेलू आय बढ़ाने में सक्षम बनाया जा सके।

इंशा ने अपनी कहानी साझा करते हुए बताया कि उन्हें बचपन से ही कपड़े डिजाइन करने और तैयार करने में रुचि रही है। लेकिन उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्थानीय सिलाई स्कूल में दाखिला लिया। उनकी प्रतिभा और रुचि एक व्यापारिक अवसर में बदल गई और आजीविका कमाने का एक माध्यम बन गई।

संस्थान में डिजाइन कोर्स पूरा करने के बाद, इंशा ने यह अनुभव किया कि वह अपना बुटीक खोलना चाहती है। उन्हें पीएमईजीपी उम्मीद ऋण मिला और इस प्रयास में, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने भी

वित्तीय सहायता प्रदान करके इस मिशन में उसकी मदद की। इस प्रकार वह अपना बुटीक स्थापित करने में सक्षम हो गई।

कभी-कभी, सीमित संसाधन और कम अवसरों के कारण सपने भी रात्रिकालीन आकाश में दूर के सितारों की तरह लगते हैं। लेकिन इंशा के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने उसे अपना सपना साकार करने में सक्षम बनाया। इंशा ने बताया कि अगर उसे योजना के तहत सब्सिडी वाला ;ण नहीं मिला होता, तो वह अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर पाती।

इंशा ने सरकार की इन व्यावसायिक योजनाओं की प्रशंसा की जो आज युवाओं की मदद करने के साथ-साथ एक नए विकसित भारत का निर्माण भी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आज केवल अमीर लोग ही तरक्की नहीं कर रहे हैं, बल्कि गरीब पृष्ठभूमि वाले और गांवों के व्यक्ति भी सफलतापूर्वक अपने व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह ऐसी योजनाओं के लिए सरकार की आभारी हैं जिनसे उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज इंशा न सिर्फ अपना कारोबार को अच्छी तरह संभाल रही हैं बल्कि अपने बुटीक में अन्य महिलाओं को भी रोजगार उपलब्ध करा रही हैं। छोटा होने के बावजूद उनका बुटीक विकास और आत्मनिर्भरता का पर्याय बन गया है।

जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित एफसीए और एफआरए मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित एफसीए और एफआरए मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न स्वीकृतियों संबंधी मामलों

के कारण लगभग 11 हजार मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजनाएं रूकी हुई हैं। उन्होंने एफसीए और एफआरए प्रक्रिया को सुगम बनाने के दृष्टिगत वन और ऊर्जा विभाग को एक समिति गठित करने के भी निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त जिलों में आवश्यक वनीकरण के दृष्टिगत उपायुक्तों और वनमण्डलाधिकारियों को भूमि चिन्हित करने को भी कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल को आत्मनिर्भर राज्य बनाने के दृष्टिगत जल विद्युत क्षमता का समुचित दोहन सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे में सभी संबंधित विभाग इन परियोजनाओं को समयबद्ध पूर्ण करने तथा लोगों को इसका समय पर लाभ उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत कार्य करें। उन्होंने 800 मेगावाट क्षमता की पार्वती और 100 मेगावाट की ऊहल तृतीय चरण जल विद्युत परियोजनाओं को वर्ष, 2024 तक पूरा करने के भी निर्देश दिए।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार प्रदेश व यहां के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही है और विद्युत परियोजनाओं में रॉयल्टी बढ़ाने का मामला इसी के दृष्टिगत उठाया गया है। उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा के लिए वे शीघ्र ही केन्द्रीय विद्युत मंत्री के साथ बैठक करेंगे ताकि प्रदेश के लिए और अधिक राजस्व सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नीति के अनुसार विद्युत परियोजनाओं को पहले 12 वर्षो में 20 प्रतिशत, अगले 18 वर्षो में 30 प्रतिशत व शेष 10 वर्षो में 40 प्रतिशत रॉयल्टी राज्य को देने का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने पांच मेगावाट से कम क्षमता की विद्युत परियोजनाओं के लिए हरसंभव मदद का भी आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के चरण-2 की भी समीक्षा की। इसके तहत राज्य सरकार 100 किलोवाट से 500 किलोवाट क्षमता की सौर विद्युत परियोजनाओं के लिए युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शीघ्र ही द्वितीय चरण की यह योजना शुरू करेगी, जिससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के समुचित अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना आरम्भ कर इसके प्रथम चरण में ई-टैक्सी की खरीद पर युवाओं को 50 प्रतिशत उपदान का प्रावधान किया है।

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, अधोसंरचना सलाहकार अनिल कपिल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, निदेशक ऊर्जा हरिकेश मीणा, मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया, राज्य विद्युत बोर्ड के निदेशक कार्मिक डॉ. अमित कुमार शर्मा, हिमऊर्जा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शुभकरण सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सुन्नी जल विद्युत परियोजना में भूमि अधिग्रहण के नियमों की हो रही अनदेखी

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि सुन्नी बांध परियोजना से प्रभावित लोगों के हितों से खिलवाड़ नही होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी मांगों को कंपनी के साथ साथ प्रदेश सरकार के समक्ष भी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बांध से प्रभावित किसी के साथ भी अन्याय नही होने दिया जाएगा।

राजीव भवन में सुन्नी जल विद्युत परियोजना की जिला शिमला व मण्डी जन चेतना जागरूकता सयुंक्त संघर्ष समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रतिभा सिंह ने कहा कि संघर्ष समिति के साथ जल्द ही एक और बैठक की जाएगी और इसमें पारित मांगो व प्रस्तावों को राज्य सरकार के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त वह जल्द ही इस क्षेत्र का दौरा भी करेंगी।

बैठक में संघर्ष समिति ने कंपनी पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस परियोजना में भूमि अधिग्रहण के नियमों की पूरी तरह अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि भूमि का मूल्य मुहाल की दर से दिया जा रहा है जो उन्हें कतई मंजूर नही है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से लगभग 2700 परिवार प्रभावित हो रहें है इसलिए उन्हें इस परियोजना में स्थाई रोजगार के साथ साथ उनकी जमीन का बाजार भाव से भूमि का उचित मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने मांग की उनकी जमीन का अधिग्रहण फेक्टर 2 के प्रावधान के तहत मुआवजा निर्धारित किया जाना चाहिए। बैठक में क्षेत्र के विकास के लिये लाडा को शामिल करने की मांग करते हुए कहा कि इस परियोजना में कोई भी स्पष्टता नही है। इसमें न तो क्षेत्र में स्कूल, अस्पताल खोलने की कोई कही गई है और न ही प्रभावित पंचायतों में सड़क पुलों के निर्माण की कोई बात कही गई है।

बैठक में परियोजना निर्माण के लिये सेवा निवृत्त भू अधिग्रहण अधिकारियों की नियुक्ति पर भी रोष व्यक्त करते हुए संघर्ष समिति ने इन अधिकारियों की जगह स्थाई राजस्व अधिकारियों को नियुक्त करने की मांग की। उन्होंने इन अधिकारियों की सेवाएं तुरंत खत्म करने या उन्हें यहां से इन पदों से हटाने की मांग की। समिति ने आरोप लगाया कि यह अधिकारी कंपनी के दबाव में प्रभावित परिवारों की समस्याओं को अनदेखा कर रहें है।

मुख्यमंत्री ने पराला में 100.42 करोड़ रुपये से निर्मित अत्याधुनिक फल विधायन संयंत्र का किया लोकार्पण

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिले के ठियोग के पराला में 100.42 करोड़ रुपये की लागत से बने अत्याधुनिक फल विधायन संयंत्र

का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि यह संयंत्र क्षेत्र के विकास में मील पत्थर साबित होगा। इस संयंत्र में वाइन, विनेगर तथा जूस तैयार किया जाएगा जिससे क्षेत्र के बागवानों को अपने उत्पाद के उचित दाम मिलेंगे तथा इनसे बनने वाले उत्पाद तैयार करने में भी तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष सेब के समर्थन मूल्य में 1.50 रुपये की ऐतिहासिक वृद्धि की गई है तथा इसे 12 रुपये प्रति किलो किया गया। उन्होंने कहा कि बागवानों की सुविधा के लिए प्रदेश में 8 ग्रेडिंग/पैकिंग हाऊस, सी.ए. व कोल्ड स्टोर भावानगर, संदासु, अणु, चौपाल, जाबली, सुन्दरनगर, दत्तनगर व खड़ापत्थर में स्थापित किए जा रहे हैं।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हाल ही के दुबई दौरे में उन्होंने निवेशकों से हिमाचल प्रदेश के बागवानी उत्पादों की मार्केटिंग की संभावनाएं तलाशने की भी अपील की है और अगले वर्ष जनवरी महीने में निवेशक हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार बागवानों को व्यापारियों और आढ़तियों के शोषण से बचाने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठा रही है ताकि उन्हें उचित फायदा हो तथा उनकी आर्थिकी भी सुदृढ़ हो। उन्होंने कहा कि इस बार सेब की खरीद किलो के आधार पर की गई है और यूनिवर्सल कार्टन व्यवस्था लागू की जा रही है ताकि बागवानों को उनके उत्पाद के उचित दाम मिल सके।

मुख्यमंत्री ने एचपीएमसी की सम्पतियों को ठीक ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए ताकि बागवानों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि एचपीएमसी के माध्यम से बागवानी औजार, खाद, कीटनाशक तथा फंफूदनाशक सस्ते दामों पर उपलब्ध करवायी जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बागवानों के हितों को सुरक्षित करने के लिए अनेक कदम उठा रही है तथा भविष्य में भी लेती रहेगी।

बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि इस यूनिट में अलग अलग उत्पाद तैयार किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार बागवानों की सुविधा के लिए अनेक योजनाएं लागू कर रही है ताकि बागवानों को आर्थिक तौर पर सम्बल किया जा सके क्योंकि बागवानी प्रदेश के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है।

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि इस फल विधायन संयंत्र से क्षेत्र में और समृद्धि आएगी तथा बागवानों को अपने उत्पाद के अच्छे दाम मिलेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकारों ने हमेशा ही बागवानों के हितों को रक्षा की है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सड़क नेटवर्क को बेहतर किया जा रहा है।

विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि वर्तमान सरकार ने बागवानों के हितों की रक्षा के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिये हैं तथा यूनिर्वसल कार्टन प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में किसानों बागवानों के हितों में अनेक निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस संयंत्र में स्थानीय लोगों को रोजगार देने में प्राथमिकता दी जाएगी।

कुल्लू में 198 करोड़ रुपये लागत की 13 परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला कुल्लू के प्रवास के दौरान जिला के लिए 198 करोड़ रुपये की 13 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दीं और कहा कि इन परियोजनाओं से स्थानीय निवासी और

पर्यटक दोनों ही लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विकास परियोजनाएं कुल्लू जिले के विकास में मील पत्थर साबित होंगी।

मुख्यमंत्री ने 20 करोड़ रुपये से की लागत से निर्मित सब्जी मंडी बंदरोल तथा 9.07 करोड़ रुपये से रायसन में ब्यास नदी पर बने डबल लेन पुल का लोकार्पण किया। उन्होंने नेहरू कुंड (बाहांग) में ब्यास नदी पर बुरवा और शनाग सम्पर्क मार्ग को जोड़ने वाले 6.44 करोड़ रुपये से बने स्टील ट्रस ब्रिज, जगतसुख नाला पर 4.07 करोड़ रुपये और चक्की नाला पर 3.37 करोड़ रुपये से बने आरसीसीटी-बीम पुलों, पतलीकूहल में 20 लाख रुपये से बने विवेकानन्द पुस्तकालय, मनाली में 7.83 करोड़ रुपये से बनी इको-फ्रेंडली मार्केट मढ़ी, सोलंगनाला में 54 लाख रुपये से तैयार वे साइड सुविधाएं और सजला में 29 लाख रुपये की लागत से निर्मित आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का उद्घाटन किया।

मुख्यमंत्री ने 130.18 करोड़ रुपये की लागत से भबेली जिंदौर सड़क के रखरखाव और टारिंग, 3.59 करोड़ रुपये की बंदरोल दीदारी शरण सड़क, 1.49 करोड़ रुपये की फ्लेन से ग्राहन सड़क और 10.86 करोड़ रुपये से ब्यास नदी के दाहिने किनारे पर ग्राम कटराई, 15 मील बड़ाग्रां बिहाल और आसपास के क्षेत्रों के लिए बाढ़ सुरक्षा कार्यो की आधारशिलाएं भी रखीं।

उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के बावजूद मुख्य पर्यटक स्थलों जैसे शिमला, मनाली और धर्मशाला में प्रदेश सरकार के सकारात्मक प्रयासों से पर्यटकों की संख्या में बढ़ौतरी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि मनाली और अन्य क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम को लेकर गलत सूचनाएं फैलाई जा रही हैं, जोकि पूरी तरह से निराधार हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस वर्ष दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने के लिए नई योजना आरम्भ करने की घोषणा की है। इसके तहत प्रदेश में एक एकीकृत विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थान खोला जाएगा। इस संस्थान में दिव्यांग छात्रों को आधारभूत स्कूली शिक्षा और महाविद्यालय स्तर की उच्च शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त छात्रों को खेलों के क्षेत्र में प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा ताकि वह पैरा ओलम्पिक्स व अन्य खेल आयोजनों में सहभागिता सुनिश्चित कर सकें।

आपदा से जल शक्ति विभाग की 11863 योजनाओं को 2132 करोड़ रुपये की क्षतिःउप-मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। हिमाचल के उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से उनके आवास पर मुलाकात की। अग्निहोत्री ने केंद्रीय मंत्री से राज्य में हाल ही में

आयी भारी प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर हिमाचल की मदद के लिए उदारता से हाथ बढ़ाने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि राज्य को हुआ नुकसान अभूतपूर्व है और इसका भारी खामियाजा जल शक्ति विभाग हिमाचल प्रदेश को भुगतना पड़ा है। जल शक्ति विभाग की 11863 योजनाओं को 2132 करोड़ रुपये की व्यापक क्षति हुई और इनमें से जल जीवन मिशन के तहत निर्मित 671 योजनाओं को भी 614 करोड़ रुपये की क्षति हुई।

अग्निहोत्री ने केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी कि जल जीवन मिशन के तहत 376 करोड़ रुपये के आवंटन में से 25 प्रतिशत यानि लगभग 96 करोड़ रुपये क्षतिग्रस्त योजनाओं की बहाली के लिए खर्च करने होंगे। इसके परिणामस्वरूप जेजेएम पर चल रहे कार्यों के लिए धन की कमी हो जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना 2023-24 (ए.ए.पी.) के अनुसार जेजेएम की तहत आवंटन 1274 करोड़ रुपये हैं, जिसे भारत सरकार द्वारा घटाकर 376 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि हिमाचल की गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसकी वार्षिक कार्य योजना को 1274 करोड़ रुपये की राशि बहाल की जाये। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि वह इस मामले को देखेंगे और हिमाचल से अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

अग्निहोत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से अनुरोध किया कि हिमाचल को जेजेएम योजनाओं को पूरा करने के लिए 6 महीने का विस्तार दिया जाये, क्योंकि पिछले तीन महीनों के दौरान जल शक्ति विभाग, हिमाचल प्रदेश का पूरा ध्यान क्षतिग्रस्त योजनाओं की बहाली पर था जिसके परिणामस्वरूप चल रहे कार्यों की प्रगति में बाधा उत्पन्न हो रही है।

अग्निहोत्री ने केंद्रीय मंत्री को याद दिलाया कि हिमाचल दौरे को दौरान उन्होंने राज्य सरकार को लेह और लद्दाख की तर्ज पर हिमाचल के बर्फीले क्षेत्र के लिए एंटी-फ्रीज जल आपूर्ति योजनाएं बनाने के निर्देश दिए थे। तदनुसार, राज्य सरकार ने जेजेएम के तहत 27 एंटी फ्रीज प्रस्तावों को मंजूरी के लिए केंद्र को भेजा है। हालांकि भरमौर, लाहौल, काजा और चांगों (जिला किन्नौर) के लिए 4 पॉयलट प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से शेष 23 प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी देने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि शेष प्रस्तावों पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री से सिंचाई एवं बाढ़ संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गयी।

अग्निहोत्री ने कहा कि जिला ऊना के बीट क्षेत्र द्वितीय चरण और कुटलैहड़ निर्वाचन क्षेत्र के लिए सतही लघु सिंचाई योजनाओं के 118.79 करोड़ रुपये के दो प्रस्ताव भारत सरकार के पास लम्बित है और उनकी तत्काल मंजूरी के लिए अनुरोध किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने इसका आश्वासन भी दिया।

मुकेश अग्निहोत्री ने काफी समय से लंबित पड़ी जिला कांगड़ा में 643 करोड़ रुपये की फीना सिंह सिंचाई परियोजना और जिला ऊना में 339 करोड़ रुपये की ब्यास बेसिन में स्वां नदी के तटीकरण को मंजूरी देने के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री का आभार प्रकट किया। उन्होंने केंद्र सरकार से धनराशि जारी करने का आग्रह किया ताकि ये कार्य शुरू किये जा सकें। उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत चल रही सिंचाई परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता जारी करने का मामला भी प्राथमिकता पर उठाया। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि वह इसे प्राथमिकता से मंजूरी देंगे। अग्निहोत्री ने नमामि गंगे के तहत चिड़गांव, रोहड़ू, सरस्वती नगर, सोलन, कंडाघाट और ददाहू में सीवरेज प्रणाली प्रदान करने के लिए 289 करोड़ रुपये के 4 प्रस्तावों को मंजूरी देने का भी अनुरोध किया। उपरोक्त प्रस्ताव भारत सरकार के पास अनुमोदन हेतु पड़े हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि प्रस्तावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। अग्निहोत्री ने पीएमकेएसवाई और बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सूक्ष्म सिंचाई योजना नादौन, उठाऊ सिंचाई योजना बरोटी-मंडप, उठाऊ सिंचाई योजना मसोत खद्द और सकरैण, मल्होड़ के लिए बाढ़ सुरक्षा कार्यों के संबंध में लंबित धनराशि जारी करने का भी अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि संतुलित धनराशि जारी करने के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।

अग्निहोत्री ने पहले से स्वीकृत 11 बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं के लिए धनराशि जारी करने पर जोर दिया। उन्होंने आगे बताया कि हिमाचल में व्यापक बारिश से नुकसान हुआ है और विभिन्न नदियों के किनारे सबसे ज्यादा तबाही हुई है। उन्होंने कहा कि इन नदियों, नालों में ऐसी घटनाएं अक्सर होती रही हैं। जल शक्ति विभाग ने केन्द्रीय जल तथा ऊर्जा अनुसंधान स्टेशन पुणे से मॉडल अध्ययन करने के बाद चैनेलाइजेशन के लिए 1795 करोड़ रुपये की एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। हिमाचल के उप-मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से हिमाचल में लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए इसे जल्द से जल्द जारी करने का अनुरोध किया। अग्निहोत्री ने ब्यास नदी के रणनीतिक महत्व को देखते हुए इसके तटीकरण के महत्व पर जोर दिया क्योंकि कुल्लू-मनाली हवाई अड्डा, चंडीगढ़ लेह राष्ट्रीय राजमार्ग इस नदी के तट पर स्थित है। उन्होंने आगे कहा कि इस नदी के तटीकरण से कुल्लू और लाहौल घाटी से बागवानी उत्पादों के परिवहन के अलावा पर्यटकों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित होगी।

अग्निहोत्री ने पीएमकेएसवाई के तहत हिमाचल प्रदेश की 14 लघु और मध्यम सिंचाई (एसएमआई) योजनाओं के लिए दो समान किस्तों (वित्त वर्ष 2023-24 के लिए) में 141.76 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए केंद्रीय मंत्री को धन्यवाद दिया। अग्निहोत्री ने हिमाचल प्रदेश की राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत 221.78 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए भी धन्यवाद दिया।

खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल होने पर 2.35 लाख का जुर्माना

शिमला/शैल। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी मंडी की अदालत ने खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल होने के मामलों में मंडी जिले के पांच थोक व खुदरा विक्रेताओं को 2 लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आये अलग-अलग मामलों में अभियोजन का पक्ष लेते हुए संबंधित प्रतिष्ठान स्वामियों को यह जुर्माना लगाया।

इस बारे में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी मंडी डॉ. मदन कुमार ने बताया कि ललित कुमार डैहर का चना दाल का सैम्पल लिया गया था जो मिसब्रांडेड पाया गया। इसमें प्रतिवादी पक्ष को 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा चेतन शर्मा तहसील चच्योट स्थित गोहर को नैकलोजाईम प्लस सिरप का सैंपल सब स्टैंडर्ड पाये जाने पर 70 हजार रुपये, निखिल कुमार गुप्ता डैहर का मुकंद बड़ी का सैंपल मिसब्रांडेड व सब स्टैंडर्ड पाये जाने पर 45 हजार रुपये, अनंत राम नेरचौक का देसी घी का सैंपल मिसब्रांडेड पाये जाने पर 30 हजार तथा निशांत शर्मा चक्कर का काजू मटर नमकीन का नमूना मिसब्रांडेड पाये जाने पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

डॉ. मदन कुमार ने कहा कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। उन्होंने मंडी जिले के सभी थोक व खुदरा विक्रेताओं को सचेत किया कि यदि खाद्य पदार्थों में किसी प्रकार की कोई कमी पायी गयी या खाद्य सैंपल निर्धारित मानकों के अनुसार परीक्षण में फेल पाये गये तो भविष्य में इसको गंभीरता से लिया जाएगा। मिलावटखोरों और पैकिंग में गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

हमने जो वादा किया था वह निभा दियाःजयराम ठाकुर

शिमला/शैल। हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिये जाने संबंधित अधिसूचना जारी होने पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय के साथ किया अपना वादा मैंने निभा दिया। सभी को शुभकामनाएं। जो हक़ 58 साल पहले मिल जाना चाहिए था। उसके लिए आज भी रोड़े अटकाने का प्रयास हुआ। राष्ट्रपति से मंज़ूरी मिलने के बाद भी हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने से रोकने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि हाटी समुदाय को यह दर्जा 1968 में ही मिल जाना चाहिये था जब उत्तराखंड के जौनसार बावर के जौनसारी समुदाय को मिला था क्योंकि हाटी समुदाय और जौनसारी समुदायों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक के साथ ही भौगोलिक समानता भी थी। तब गिरिपार के साथ अन्याय हुआ था।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जिस समय सरकार को हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के प्रावधानों में अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए थी उस समय कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने उस कानून को अटकाने, भटकाने और लटकाने के तरीक़े खोजने में अपनी ऊर्जा खर्च कर रही थी। आखिरकार स्पष्टीकरण के नाम पर इस क़ानून को लागू करने से रोकने का प्रयास किया गया। जबकि हमारी सरकार के समय बने ड्राफ्ट में ही सरकार द्वारा पूछे गये तीनों सवालों के स्पष्ट जवाब थे। सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने में देरी से हज़ारों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ।

जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने गिरिपार के क्षेत्र के लोगों का दुःख समझा और हाटी समुदाय जनजातीय दर्जा दिलाने की दिशा में युद्ध स्तर पर काम किया। मुख्यमंत्री के रूप में एक नोडल एजेंसी का गठन किया। जो हाटी समुदाय से जुड़े तमाम तथ्यों की जानकारी जुटा सके। नोडल एजेंसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी शोध पत्रों को एकत्रित कर क्षेत्र की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर हर पहलू को जांचा परखा और वर्ष 2021 में रिपोर्ट को हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट द्वारा केंद्र सरकार को भेजी। इस रिपोर्ट पर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संज्ञान लिया गया और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने हाटी जनजाति को 13 अप्रैल 2022 को एक कबीले के रूप में पंजीकृत किया। इसके बाद 16 दिसंबर 2022 को केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा से 26 जुलाई 2023 को राज्यसभा से भी पारित होने के बाद 04 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। 01 जनवरी 2024 को हिमाचल सरकार द्वारा इसकी अधिसूचना जारी हुई।

जनविरोधी निर्णयों व कर्ज के लिए जानी जाएगी कांग्रेस सरकारःरणधीर शर्मा

शिमला/शैल। भाजपा प्रदेश मीडिया संयोजक एवं विधायक रणधीर शर्मा ने प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार का 12 महाने का कार्यकाल जहां जन विरोधी निर्णयों के लिए जाना जायेगा, वहीं 12 हजार करोड़ कर्ज लेने के लिए भी याद किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पर्यटकों के सम्बध में मुख्यमंत्री ने जो ब्यान दिया है, उसे भाजपा गैर जिम्मेदाराना मानती हैं। हिमाचल की सरकार द्वारा लिये गये निर्णय और मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया ब्यान प्रदेश की बिगड़ रही कानून व्यवस्था को और बिगाड़ने में सहायक सिद्ध होंगे। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने ब्यान दिया और जिन शब्दो का इस्तेमाल उन्होंने किया वह किसी भी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देते, वहीं मुख्यमंत्री पद की गरीमा को भी ठेस पहुंचाई गई। उनके द्वारा दिए गए ब्यान में कहा गया कि जो पर्यटक झूमेंगें उन्हें पुलिस होटल छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ये सभी निर्णय नशे को बढ़ावा देने की ओर इशारा कर रहें हैं।

विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पाटी कांग्रेस के मुख्यमंत्री के इन ब्यानों को दुर्भाग्यपूर्ण मानती हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के ब्यान से अगर लोकल व्यक्ति अगर ऐसी अवस्था में पाया जाये तो उन्हें सख्ती से देखा जायेगा। इससे तो साफ दिखता हैं कि हिमाचल में दोहरी कानून व्यवस्था अपनाई जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश वासियों के अलग कानून और पर्यटकों के लिए अलग। मुख्यमंत्री के ऐसे ब्यान पर शंका है कि इस ब्यान के बाद पर्यटकों के साथ अनेक सामाजिक व अपराधिक तत्व प्रदेश में घुस सकते हैं और मुख्यमंत्री के इस ब्यान का फायदा उठा कर प्रदेश की कानून व्यवस्था को भी बिगाड़ने का प्रयास कर सकते है।

उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश सरकार से यह मांग करती हैं कि मुख्यमंत्री को यह ब्यान वापिस लेना चाहिए और पुलिस अपनी कार्यवाही करें।

उन्होंने ने कहा कि इन 12 महीनों में 1 हजार से अधिक संस्थान डिनोटिफाई किए गए, 6रूपये डीजल मंहगा किया गया, सीमेंट की बोरी 10 रूपये बढ़ाई गई, 19 प्रतिशत बिजली में बढौतरी की गई। राजस्व विभाग के अंतर्गत स्टाप डयूटी में बेतहाशा वृद्धि की गई।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया, मंदिरों में दर्शनों पर श्रद्धालुओं पर फीस लगाने का निर्णय लिये। रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा 12 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेने के बाद भी हालात ऐसे हैं कि सरकारी खजाने में सिर्फ 23 करोड़ रूपये ही बचे हैं।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की महिलाएं इस सरकार से एक साल से 1500 रूपये महीने का इंतजार कर रहीं, युवा नौकरी का इंतजार कर रहें, किसान गोबर और दूध खरीदने का इंतजार कर रहें, इसी तरह से कर्मचारी तनख्वाह तथा रिटार्यड कर्मचारी पेंशन का इंतजार करते रहें।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायक भी मंत्री बनने का इंतजार करते रहें परन्तु साल खत्म होने के उपरान्त मंत्री तो बन गये अब विभागों का इंतजार कर हैं।

विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा इस जन विरोधी सरकार का, जनता को इंतजार कराने वाली सरकार का और गांरटी व वायदे देकर चुनाव जितने वाली सरकार का विरोध करती हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी मुद्दों को लोकसभा चुनाव में उठाएंगें।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाषः 0177-2805015, 94180-15015 फैक्सः 2805015

कुंडू प्रकरण में सरकार और विपक्ष दोनों की विश्वसनीयता सवालों में

शिमला/शैल। डीजीपी कुंडू ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में 29 दिसंबर को एसएलपी दायर कर दी है। जिसमें उच्च न्यायालय ने डीजीपी और एसपी कांगड़ा को उनके पदों से हटाने के निर्देश दिए थे। स्मरणीय है कि उच्च न्यायालय ने यह आदेश पालमपुर के एक कारोबारी निशांत शर्मा की 28-10-23 को आयी शिकायत का स्वत: संज्ञान लेते हुए दायर हुई याचिका पर किए हैं। निशांत शर्मा ने 28-10- 2023 को यह शिकायत हिमाचल सरकार, डीजीपी, उच्च न्यायालय और कुछ अन्य को भेजी थी। इसमें डीजीपी के खिलाफ भी गंभीर आरोप लगाए गए थे। लेकिन इस शिकायत पर सरकार द्वारा कुछ नहीं किया गया। बल्कि डीजीपी ने उनके खिलाफ आयी शिकायत पर 4-11-23 को निशांत शर्मा के खिलाफ ही

- **मुख्यमंत्री फैसला ही पढ़ते रहे और कुंडू सर्वोच्च न्यायालय भी पहुंच गये**
- **क्या आम आदमी इस व्यवस्था से सुरक्षित रह पायेगा?**

एक एफआईआर दर्ज करवा दी। इस पर उच्च न्यायालय ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया और तब निशांत की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद एसपी कांगड़ा और शिमला से रिपोर्ट तलब की। यह रपट अदालत ने सरकार को भी भेजी लेकिन सरकार ने इसके बाद भी कुछ नहीं किया। सरकार द्वारा इस तरह आंखें बंद कर लेना अपने में ही कई सवाल खड़े कर जाता है। क्योंकि शिकायतकर्ता ने अपने को इन लोगों से जान और माल के खतरे का गंभीर आरोप लगाया हुआ था। सरकार की बेरुखी के बाद उच्च न्यायालय ने 26 दिसंबर को निर्देश दिए की डीजीपी और एसपी को तुरंत अपने पदों से हटकर अन्यत्र तैनात किया जाए जहां वह जांच को प्रभावित न कर सके। क्योंकि डीजीपी के पद पर बने रहते उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच हो पाना संभव नहीं हो सकता।

डीजीपी को पद से हटाने के निर्देश उच्च न्यायालय ने 26 दिसंबर को दिए थे और यह निर्देश उसी दिन मुख्यमंत्री के संज्ञान में आ गए थे। लेकिन मुख्यमंत्री की इस मामले पर प्रतिक्रिया 29 दिसंबर को आयी। जिसमें उन्होंने यह कहा कि वह उच्च न्यायालय के फैसले को पढ़ने के बाद प्रतिक्रिया देंगे। 29 को जब मुख्यमंत्री यह प्रतिक्रिया दे रहे थे तब तक शायद कुंडू सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर चुके थे। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल की भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है। जबकि हर मामले उनकी प्रतिक्रियाएं आती हैं। जिस मामले में एक डीजीपी के खिलाफ कोई यह शिकायत करें कि उसे डीजीपी से ही जान और माल का खतरा है और ऐसे मामले में सरकार उच्च न्यायालय के फैसले पर भी खामोश बैठी रहे तथा विपक्ष भी मौन साध ले तो स्वभाविक है कि ऐसी व्यवस्था परिवर्तन पर आम आदमी कैसे और कितना विश्वास कर पायेगा? इस मामले में सरकार और विपक्ष दोनों का ही राजनीतिक आचरण सवालों के घेरे में आ खड़ा हुआ है। इस आचरण से यह संदेश चला गया है की उच्च पदस्थों के बारे में इस व्यवस्था से कोई उम्मीद करना संभव नहीं होगा। क्योंकि जब शिकायतकर्ता की शिकायत पर ही किसी जांच से पहले उसी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाये तो ऐसा व्यक्ति किस से न्याय की उम्मीद करेगा।

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला क्या आता है और उच्च न्यायालय क्या संज्ञान लेता है यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। लेकिन इससे यह स्पष्ट हो गया है कि शीर्ष अफसरसाही ही सरकार पर पूरी तरह प्रभावी है।

आर.टी.आई. आवेदन पर नगर निगम शिमला

.....पृष्ठ 1 का शेष

संबंधित सूचना अधिकारी को कड़ा पत्र लिखना पड़ जाये तो स्वभाविक रूप से संद्धर्भित निर्माण और संबंधित निगम प्रशासन को लेकर शंकाएं उभरेगी ही। स्मरणीय है कि एक आरटीआई एक्टीविस्ट देवाशीष भट्टाचार्य ने शिमला के मैहली क्षेत्र में बने एक निर्माण की फोटो के साथ नगर निगम से उसके संबंध में कुछ जानकारियां मांगी। यह जानकारियां 18-10-2023 को मांगी गयी थी। जब इनका जवाब तय समय के भीतर नहीं आया तो देवाशीष ने इसकी अपील दायर कर दी। इस अपील पर 12 -12-2023 को संबंधित अपील अधिकारी का फैसला आया। जिसमें अपील अधिकारी ने आवेदक को निशुल्क जानकारी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जब आरटीआई आवेदनों पर तय समय के भीतर सूचना न दिये जाने पर आवेदक अपील में जाने के लिये बाध्य कर दिया जाता है तो उस आरटीआई की अवधारणा को ही आघात पहुंचता है। इस संबंध में डाली गयी आरटीआई और उस पर अपील अधिकारी के निर्देश पाठकों के सामने यथास्थिति रखे जा रहे हैं।

SPEED POST 18.10.2023

(Application Under Section 6 of The RTI Act 2005)

To,
The Public Information Officer,
O/O The Commissioner,
Shimla Municipal Corporation,
Shimla, H.P.-171001

Sir,

Kindly find enclosed the copies of the three pictures of a building named as Hari Vishram Bhawan, Lower Panthaghati, Mehli Shoghi Bye Pass Road, Shimla-171009.

You are requested to provide the following information w.r.t. the said above mentioned vbuilding:

1. Kindly provide the Khasra numbers on which the said building exists as per your records.
2. Kindly provide the details about the said building e.g. whether this building has been approved for residential purposes or commercial purposes as per your records.
3. Kindly provide the details of the ownership of this building as per your records.
4. Kindly provide the certified copies of all the objections, clearances, correspondences related to the lawful construction norms etc. related to the said building named as Hari Vishram Bhawan as per your records.
5. Kindly provide the details of the violations, if any, relating to the building plans and norms of Shimla w.r.t. the said building as per the records.

Kindly correspond through email or Registered Post to avoid delay.
Kindly find enclosed an IPO no. 57F 591862 of Rs.10/- as the requisite fees of the instant RTI application.

Thanking you,
Sincerely yours,
Dev Ashish

(Dev Ashish Bhattacharya),
B-5, Pocket-7, Block-54, Kendriya Vihar-II,
Sector-82, Noida, U.P.-201304,
Mobile: 9810108363,
Email ID: rtidab@gmail.com

IN THE COURT OF FIRST APPELLATE AUTHORITY (UNDER THE RTI ACT, 2005)-CUM-JOINT COMMISSIONER, MUNICIPAL CORPORATION SHIMLA.

Appeal No. 53/RTI/23
Dy. No. 6629/MU/2023
Date of Institution 26.10.2023
Date of Order 12.12.2023

Sh. Dev Ashish Bhattacharya,
B-5, Pocket-7, Block-54,
Kendriya Vihar-II, Sector-82, Noida,
UP-201304,
M.No 9810108363

... Appellant.

Versus

The Public Information Officer-cum-Architect Planner, M.C. Shimla.

... Respondent.

Present: Applicant was not present.

Sh. Mahboob Sheikh- PIO-cum-Architect Planner, M.C. Shimla.

ORDER

Present appeal has been filed by the appellant against the PIO-cum-Architect Planner, M.C. Shimla.

1. That present appeal has been filed by the appellant against PIO-cum-Architect Planner, M.C. Shimla.
2. Brief facts of the appeal are that the appellant filed an application on dated 18.10.2023. In the said application the appellant sought following information:-
   - (i) Kindly provide the Kh. Nos. on which the said building exists as per your record.
   - (ii) Kindly provide the details about the said building e.g. whether this building has been approved for residential purposes or commercial purposes as per your records.
   - (iii) Kindly provide the details of the ownership of this building as per your records.
   - (iv) Kindly provide the certified copies of all objections, clearances, correspondences related to the lawful construction norms etc. related to the said building named as Hari Vishram Bhawan as per your records.
   - (v) Kindly provide the details of the violations, if any, relating to the building plans and norms of Shimla w.r.t. the said building as per the records.
3. That the appellant has stated in his appeal that PIO-cum-Architect Planner, M.C. Shimla has not supplied the sought information.
4. That not being satisfied with the inaction of the PIO-cum-Architect Planner, M.C. Shimla, the appellant preferred the present appeal.
5. That on the receipt of appeal, notices were issued to the parties on 28.11.2023 for the hearing of the appeal on 12.12.2023.

The perusal of the record placed before me and after hearing the appellant in detail, it is evident that the information sought by the appellant has not been provided to him by the PIO-cum-Architect Planner, M.C. Shimla.

The PIO-cum-Architect Planner, M.C. Shimla is hereby strictly warned that all application be dealt within the stipulated period of 30 days. The PIO-cum-Architect Planner, M.C. Shimla is directed to supply the available information to the appellant free of cost within next seven days.

With the above observations, the present appeal stands disposed of.

It the appellant is not satisfied, he may file Second Appeal before the State Information Commission U/S 19 (3) of RTI Act, 2005 at Keonthal Complex, Khalini Shimla-2. The case file be consigned to Record Room of M.C. Shimla after due completion. Copy of this order be sent to the PIO and appellant.

Announced.

(Dr. Bhuwan Sharma)
First Appellate Authority-
Cum-Joint Commissioner,
M.C. Shimla.